जाती है, अतः वेतन के संशोधन वेतनमान लागू कर दिये जाने के कारण, जो संशोधन पूर्व के वेतनमानों से काफी ऊंचे हैं, परिवार पेंशन की मात्रा में वृद्धि हुई है ।

(iv) परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत उसी दर पर दी जाती है जिस दर पर सेवारत कर्मचारियों को दी जाती है । इस समय 1-1-1987 से परिवार पेंशन की राशि पर 8 प्रतिशत की दर पर मंहगाई राहत का भुगतान किया जाता है ।

रेल दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरियां

3804. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरी देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की और कौन-कौन सी कल्याण योजनायें हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) गाड़ी दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले अन्य व्यक्तियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि वैध उत्तराधिकारियों को भारतीय रेल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान धन के रूप में किया जाता है।

दिल्ली के स्कूलों में विद्युत कनेक्शन

3805. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कुछ स्कूलों में विद्युत कनेक्शन न होने के कारण विद्यार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या ऐसे स्कूलों में, जहां विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, तम्बुओं में चल रहे स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों में सामान्यता बिजली का कनेक्शन प्रदान किया जाता है ।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम के कुछ स्कूलों में जो तम्बुओं में चल रहे हैं उनमें बिजली के कनेक्शन प्रदान नहीं किये गये हैं । जैसे ही तम्बूओं के स्थान पर पक्के भवन उपलब्ध हो जाते हैं बिजली के कनेक्शन प्रदान कर दिये जाते हैं ।

गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रहमपुरी, नई दिल्ली के लिये भवन

3806. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालय में एक मामला लंबित होने के कारण गवर्नमेंट सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, ब्रहम-पुरी, दिल्ली-110053 के भवन का निर्माण कार्य नहीं किया जा सका अथवा उसके भवन के निर्माण के लिए अब तक कोई अनुमति नही दी गई है ;

(ख) क्या न्यायालय में लंबित मामले का शीघ्र निपटान किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, स्कूल भवन के लिए आवंटित भूमि के झगड़े वाले भाग को छोड़कर शौचालय खंडों, चारदीवारी के निर्माण कार्य की मंजूरी दे दी गयी है।

(ख) न्यायालय मामलों के संबंध में यथा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया का दिल्ली प्रशासन द्वारा पालन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Central aid for sports fields in Punjab

3807. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Miinster of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the State Government of Punjab for financial assistance to develop sports fields in that State;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the amount of funds released to Punjab for the purpose during the year 1986-87?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) and (b) Central Government have received in 1987-88 a proposal from the State Government of Punjab for financial assistance for development of play fields at 20 places. Central assistance of Rs. 10 lakhs has been approved and first instalment of Rs. 5 lakhs has been released. Each playfield has been approved an amount of Rs. 50,000, the maximum admissible under the scheme of central assistance. These 20 playfields are at Sarhali, Baba Bakala, Rampur, Talwandi Sebo, Lambi, Saidonke, Daroli Bhai, Azamwala, Unikhera, Morh, Babehali, Balachaur, Kaherwili. Mawn Pind Donowal, Bagli Kalan, Ghagga, Bhadson, Khizerabad, Agampur, Bakshiwala.

(c) During 1986-87, central assistance of Rs. 4.50 lakhs was approved for development of 9 playfields. Rs. 2.25 lakhs was released as first instalment. 2nd instalment will be released on the receipt of Utilization Certificates and progress report.

Revision of pay scales of Technical Teachers

3808. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to revise the pay scales of technical teachers, viz. those who do not come under Universities but under the Directorates of Technical Education and various Boards in view of special emphasis on vocational streams of education; and

(b) if so, what are the measures so far taken in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) In 1984, a National Expert Committee was appointed to look into the quesion of revision of pay scale of teachers in technical institutions. The Commitee has now submitted its report and the recommendaions of the Committee are being examined by he Government.

National Highways in the Country

3809. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the condition of the National Highways is not in a uniform stage of up-keep and maintenance in the various States of the country, though the Centre is financing the National Highways;

(b) whether Government propose to take any steps to make all National Highways of the country to accommodate four lane traffic (two up and two down); and